हिमाचल का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक समाचार पत्र

आप का सामना

हक़ीक़त से

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,चंडीगढ़,दिल्ली, में प्रसारित

पोस्टल रजि.नंबर एचपी/33/ एसएमएल
(31 दिसंबर 2024 तक मान्य)

वर्ष- 14 अंक-20 शिमला शुक्रवार,01 l 07 ekp 2024 आरएनआई एचपीएवआईएन@2010@41180 कुल पृष्ठ-6 मूल्य- 5 रू०

शिमला में पुलिस सहायता कक्ष के सामने गंडासी से युवक की हत्या

vkdk f'keykA राजधानी शिमला के मालरोड पर पुलिस सहायता कक्ष के सामने एक युवक की तेजधार हथियार (गंडासी) से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मनीष (21) निवासी कोटी, कुपवी (चौपाल) के रूप में हुई है। मनीष करीब एक साल से मालरोड के एक रेस्तरां में काम कर रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक रेस्तरां के साथ लगते कैफे में दिसंबर 2023 से काम कर रहे रानिया सिरसा (हरियाणा) के सितेंद्र पाल सिंह ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैफे में चोरी का प्रयास कर रहा था।

इस बीच साथ लगते रेस्तरां में सो रहे मनीष को इसकी भनक लगी तो वह जाग गया। जैसे ही मनीष बाहर निकला तो आरोपी ने गंडासी से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वारदात रविवार रात 1 बजकर 42 मिनट की है। हमले के बाद मनीष लहुलूहान हालत में मदद के लिए मालरोड स्थित पुलिस सहायता कक्ष की ओर दौड़ा। रेस्तरां से 50 मीटर की दूरी पर वह दो जगह गिरा। जिस गंडासी से आरा.`पी ने हमला किया, उसे मनीष साथ लाया था। उसने गंडासी पुलिस सहायता कक्ष की तरफ फेंकी और इससे दरवाजे का शीशा टूट गया। शीशा टूटने की आवाज सुनकर पुलिस कर्मी बाहर निकले तो देखा मनीष लहुलूहान हालत में जमीन पर पड़ा था। खून बह रहा था। पुलिस कर्मियों ने मनीष को उठाया और आईजीएमसी ले गए। यहां उपचार के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों के मुताबिक अत्यधिक खून बहने से मनीष की मौत हो गई। बताते हैं कि मनीष रेस्तरां में पार्ट टाइम नौकरी करने के साथ–साथ कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा था। परिवार का वह इकलौता बेटा था। हत्या करने के बाद फरार आरा.`पी को पुलिस ने गिरतार कर लिया है। शिमला पुलिस की टीम ने आरोपी सितेंद्र पाल सिंह (29) निवासी मकान नंबर 89, वार्ड नंबर–5 रनिया, सिरसा हरियाणा को मंगलवार सुबह करीब छह बजे चंडीगढ़ में दबोचा। आरोपी को वहां से शिमला लाया गया। आरा.`पी ने वारदात को अंजाम क्यों दिया, पुलिस इसके बारे में पता लगाने में जुट गई है।

फरार हुए आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें करीब 28 घंटों से जुटी थी। आरोपी हुलिया बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास करता रहा, लेकिन एक यूपीआई ट्रांजेक्शन ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

ef=eMy dh cBd e lok yk[k dfe;k dk ,d vçy l c<k gvk ekun;]lkro jkT; foÙk vk;kx d xBu dk e tjh

vkdk f'keykA हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर, पंचायत, शहरी निकाय जन प्रतिनिधि, नंबरदार, सिलाई टीचर, स्रूष्ट व कंप्यूटर टीचर, मल्टी टॉस्क वर्कर इत्यादि को एक अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2024–25 के बजट भाषण में की है। इससे लगभग सवा लाख लोग लाभान्वित होंगे।

बजट भाषण में सीएम की ओर से की गई घोषणा के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों, एसएमसी शिक्षकों, मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायतों व नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के .ष्टिगत सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।

बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजी.त डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति–2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।

मंत्रिमंडल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी स्वी.ति प्रदान की। स्कूल के मेधावी विद्यार्थी अब खुद लैपटॉप खरीदेंगे।

70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का अस्पताल में निशुल्क उपचार होगा।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

वहीं सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट में 10वीं व 12वीं कक्षा के टॉपर बच्चों को लैपटॉप के लिए 25 हजार रुपए नकद देने का निर्णय लिया गया। पूर्व में मेधावी छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक जैसे लैपटॉप दिए जाते थे।

मगर सुक्खू सरकार ने बच्चों की उनकी पसंद का लैपटॉप या फिर टैबलेट की खरीद देने के मकसद से नकद राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि 10500 बच्चों को दी जाएगी। लैपटॉप और टैबलेट खरीद के बिल विभाग को देने के बाद यह राशि बच्चों के बैंक खातों में डाली जाएगी।

एक अप्रैल से एकल नारी को मकान बनाने को 3–3 लाख

कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने एक नारी को मकान बनाने के लिए एक अप्रैल 2024 से तीन–तीन लाख देने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।

प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई। पूर्व पॉलिसी के अनुसार, 100 प्रतिशत डॉक्टरों को कठिन जिलों में पोस्टिंग की जानी थी। मगर कैबिनेट ने 50 फीसदी डॉक्टरों को ही हार्ड एरिया वाले जिलों में तैनाती देने का निर्णय लिया है। शेष 50 प्रतिशत डॉक्टरों को सामान्य एरिया में भेजा जाएगा।

कैबिनेट ने 2024–25 के बजट को भी पास किया है।

सोनिया, खरगे की न के बाद भी गए थे अयोध्या के राम मंदिर, क्या कट्टर सनातनी हैं विक्रमादित्य?

vkdk f'keykA हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन जीत गए हैं। बुधवार को कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया । उन्होंने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। जानकारों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने अपने ट्वीट में कहा है कि विक्रमादित्य सिंह, कट्टर सनातनी हैं। वे अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे थे। खास बात है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अयोध्या नहीं पहुंचा था। हिमाचल प्रदेश से केवल विक्रमादित्य सिंह ही नहीं, बल्कि उनके साथी विधायक सुधीर शर्मा ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था।

राज्यसभा की हार ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर कर दिया है। चुनाव के बाद से ही प्रदेश में कांग्रेस के दो धड़े नजर आ रहे थे। इनमें एक धड़ा वीरभद्र सिंह समर्थकों का है, तो दूसरा धड़ा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। अयोध्या में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने में असमर्थता जताई थी। खास बात है कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह,विधायक सुधीर शर्मा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंच गए थे। तब से ही कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था।

शिक्षा में सरकारी स्कूल उत्कृष्टता के उच्च मानक कर रहे स्थापित : शिक्षा मंत्री

vkdk f'keykA शिक्षा मंत्री रोहित ने कहा कि आजादी के समय हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 8 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अग्रणी राज्यों में शुमार होने का श्रेय राज्य के सरकारी स्कूलों द्वारा स्थापित उच्च मानकों को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार ने भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्व. विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करके उच्च मुकाम हासिल किया।

शिक्षा मंत्री ने यहां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के सहयोग से क्रैक अकादमी द्वारा राज्य के सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में मेरे शहर के 100 रतन छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह अकादमी सिविल सेवा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करती है। यह अकादमी हिमाचल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 100 छात्रों का चयन कर इन्हें छात्रवृति प्रदान करेगी। जिसके लिए प्रथम मई, 2024 को छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस छात्रवृत्ति से प्रदेश के मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा, जो आर्थिक या अन्य संसाधनों की कमी के चलते कोचिंग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते।

रोहित ने कहा कि हिमाचल के सरक.ारी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी देश, दुनिया व प्रदेश के उच्च संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा प्रणाली के कारण ही हिमाचल में प्रति व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का अनुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है और हिमाचल प्रति व्यक्ति आय के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचना के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 15 लाख छात्र हैं, जिनमें से 55 प्रतिशत सरकारी संस्थानों में हैं। राज्य सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अधिक विद्यार्थी जोडने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अन्तर्गत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल भी बना रही है।

इस अवसर पर महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान, पार्षद उमंग बंगा, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दीपक धीमान, क्रैक अकादमी के सीईओ नीरज कंसल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उनकी बात सुननी चाहिए थी,बागी विधायकों का नाराज होना जायज

vkdk f'keykA हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधायकों के निष्कासन पर जल्दबाजी की गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है।

गुरुवार सुबह अपने निजी आवास हॉली लॉज में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि इन छह विधायकों का नाराज होना जायज है। उन्हें बैठाकर उनकी बात को सुना जाना चाहिए था।

शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था होगी शुरू : मुख्यमंत्री

vkdlk f'keykA मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लौहारब के 15.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टुटू में पांच करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए बस सेवा आरम्भ की जाएगी और महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024–25 में सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग और उनके लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था की शुरूआत का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विक. सित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पढ़ने–लिखने की संस्ृति विकसित करने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए गए हैं।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस ललित कला महाविद्यालय की नींव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी। वर्तमान में संस्थान में 17 राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संस्थान में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी डे–बोर्डिंग स्कूल, क्लस्टर प्रणाली, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना, मुख्यमंत्री सुख–शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना, दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न योजनाओं, आपदा राहत पैकेज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सश. क्तिकरण, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित विभिन्न विषयों के बारे में सरकार के प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सु.ढ़ करने के लिए निरन्तर प्रयास जारी है और कई प्रभावी कदम इस दिशा में उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की गई है।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में एक मॉडल क्षेत्र के रूप में उभर रहा है तथा विकास कार्यों को निरन्तर गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में 170 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगें भी प्रस्तुत कीं।

महाविद्यालय की प्रधानाचार्य कामायनी बिष्ट व स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान जीत सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

खण्ड कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर पंचायत समिति अध्यक्ष सरोज शर्मा, पूर्व विधायक सोहन लाल व चिरंजी लाल, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी चन्द्रशेखर शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी, संगठन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिक. ारी उपस्थित थे।

e[;e=h u dykx l fd;k bfnjk xkèkh l;kjh cguk lEeku fufèk ;ktuk dk 'kHkkjHk]efgykvk dk çfrekg 1500 #i; feyxh i'ku

vkdlk dykx A मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल–स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल–स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला लाहौल–स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे–बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जिला लाहौल–स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी।

जुले कहकर अपने भाषण की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में –9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं।

जिला लाहौल–स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ–साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी 2024 से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने उन्हें खाली खजाना विरासत में दिया, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। सरकार ने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी क्योंकि कर्ज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और राजस्व में वृद्धि के उपाय तलाशे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है इसलिए अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना।

विधायक रवि ठाकुर ने 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल–स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है और सभी वर्गों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू किया है तथा महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की पहल भी लाहौल–स्पीति से कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।

विधायक रवि ठाकुर ने 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने जिलावासियों को लाहौल शरद उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यह एक आपसी मेल–जोल तथा यहां की समृद्ध संस्ृति को प्रदर्शित करने का मंच है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया।

इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गेलसन ठाकुर, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी, निद. ेशक ईसोमसा प्रदीप ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

हमीरपुर भाजपा मंडल के त्रिदेव सम्मेलन में अनुराग ठाकुर ने की शिरकत, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला

vkdlk gehjijA केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी खुद अपना होश खो बैठे हैं। क्या बयान देते हैं और उसके बाद हंसी का पात्र बनते हैं। अबकी बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश से अपना खाता तक भी नहीं खोल पाएगी।

त्रिदेव सम्मेलन में उपस्थित त्रिदेवों को संबोधित करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा में सबसे बड़ी भूमिका ही संगठन और कार्यकर्ता की होती है। पार्टी के त्रिदेव वह कार्यकर्ता होते हैं जो मतदान केंद्र को सशक्त करते हैं और अबकी बार त्रिदेव ऐसा संकल्प लेकर चले हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को धराशायी किया है। ठीक उसी तरह हर पोलिंग बूथ पर पार्टी के पक्ष में 370 वोट अधिक बढ़ाने की मुहिम सब मिलकर चलाएंगे।

भाजपा 370 सीटें और एनडीए 400 सीटें जीतेगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा जनता में बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस ने जनता को ठगा है। अपने ही किए वायदों से कांग्रेस मुकर गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ने त्रिदेव सम्मलेन के बाद खेतों में पहुंचकर ट्रैक्टर चलाया। इस दौरान उनके साथ किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिल काकू और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हर्ष महाजन,मनु को मात देने वाले आज तक नहीं हारे कोई भी चुनाव

vkdlk f'keykA हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर भाजपा के हर्ष महाजन ने राज्यसभा चुनाव जीत लिया है।

दोनों दलों के प्रत्याशियों को 34–34 वोट मिले थे। इसके बाद पर्ची से फैसला हुआ जिसमें भाजपा ने बाजी मारी।

जानकारी के अनुसार हर्ष महाजन आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। वर्तमान में महाजन भाजपा कोर ग्रुप के सदस्य हैं।

हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के करीबियों में से एक थे और उनके प्रमुख रणनीतिकार माने जाते थे।

हर्ष तीन बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। वीरभद्र सरकार में पशुपालन मंत्री भी रहे। वह राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हर्ष महाजन ने अपनी जीत के बाद कहा कि कांग्रेस की सरकार बहुमत खो चुकी है। अगर शर्म है तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। एक हते या एक महीने के अंदर प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी।

महाजन ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को दिया।

हर्ष महाजन वर्ष 1993 से 2007 तक तीन बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे।

वर्ष 2007 के बाद से महाजन ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के चुनावों का जिम्मा संभाला था।

1993 में पहली बार विधायक बने महाजन तत्कालीन सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। 1998 में प्रदेश कांग्रेस का चीफ व्हीप चुना गया।

2003 में महाजन कैबिनेट मंत्री बने थे। वर्ष 1986 से 1996 तक महाजन प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2012 में राज्य सहकारी बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वह कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे।

हर्ष महाजन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री देस राज महाजन के बेटे हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर 1955 को चंबा में हुआ था। महाजन ने बीकॉम और एमबीए की है। उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। 7 जून 1983 को उनकी शादी उमा सिंह से हुई। 28 सितंबर 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान हर्ष महाजन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।

दलबदल कानून के तहत बागी छह कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द

vkdlk f'keykA पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि सुखविंद्र सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पर्यवेक्षकों ने एलान किया कि हाईकमान ने सुक्खू के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और उन्हें क्लीन चिट दे दी है। पर्यवेक्षकों के मनाने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा भी वापस ले लिया। इसके बाद वह कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। उधर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दलबदल कानून के तहत बागी छह कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। इसके तुरंत बाद बागी विधायकों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दे दी है। गुरुवार सुबह 11:00 बजे विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने दलबदल कानून के तहत बागी विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल की सदस्यता रद्द करने का एलान किया। व्हिप जारी करने के बावजूद बजट पारित करने के दिन विधानसभा में मौजूद न रहने पर इन पर कार्रवाई की गई है। पठानिया ने कहा कि छह कांग्रेस विधायक जानबूझकर गैरहाजिर रहे। दलबदल कानून के तहत वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया गया है। उन्होंने कहा कि खरीद–फरोख्त की अलोकतांत्रिक परंपरा को हतोत्साहित करना भी मद्देनजर रखा गया है।

वहीं, राजनीतिक हलचल के बाद दो दिन से शिमला में डटे हाईकमान की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पांच साल तक सत्ता में बनी रहेगी।

अब अदालत की अनुमति के बिना नहीं मिलेगी पैरोल, राम रहीम को बड़ा झटका हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकारा

pMhx<A गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार–बार पैरोल मिल रही है? बाकी कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार–बार हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार बार पैरोल/फरलो देने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है, काफी संख्या में लोग जेलों में है जो पैरोल/फरलो का इंतजार कर रहे है और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा।

सरकार ने कहा कि नियमों के तहत ही राम रहीम को पैरोल दी जा रही है और जहां तक बाकी कैदियों का मामला है तो हर केस पर विचार करने के बाद पैरोल का निर्णय लिया जाता है। कोर्ट के कुछ फैसलों को हवाला देकर कहा गया कि राम रहीम हार्ड कोर अपराधी नहीं है और ऐसे में उसे पैरोल दी जा सकती है।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर बताया जाए कि सरकार के पास कितने कैदियों को पैरोल और फरलो की अर्जियां आई हैं और उनमें से कितनों को पैरोल और फरलो दी गई है।

कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस केस में डेरा मुखी को सजा सुनाई गई है उसी अपराध के अन्य कितने दोषियों को आज तक कितनी बार पैरोल और फरलो दी गई है और कितनी अर्जियां अब तक पेंडिंग हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब राम रहीम को अदालत की मंजूरी के बिना पैरोल नहीं दी जाएगी।

चंडीगढ़ पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई विशेष अदालत में चल रहे सबसे ज्यादा मामले

pMhx<A सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे 69 मामलों में से 23 मामलों में पुलिसकर्मी शामिल हैं। 23 में से 20 मामले चंडीगढ़ पुलिसकर्मियों के खिलाफ चल रहे हैं, जिनमें कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। बाकी के मामलों में तीन राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिसकर्मी शामिल हैं। सबसे ज्यादा मामले पुलिसकर्मियों के खिलाफ हैं।

सबसे पुराना मामला 2015 में गिरतार ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) के डीएसपी आरसी मीना के खिलाफ 40 लाख रुपये की रिश्वत लेने का मामला है। यह मामला लंबित मामलों में सबसे पुराना मामला है। सूत्रों के अनुसार पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत में चल रहे मामलों में 95 फीसदी से अधिक पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। एक या दो मामलों को छोड़कर किसी भी पुलिसकर्मी को अदालत ने बरी नहीं किया है। पुलिस के खिलाफ सजा की दर 95 फीसदी से अधिक है।

2015 के बाद से 32 से अधिक मामले पुलिस के खिलाफ

सीबीआई अदालत में 2015 के बाद से 32 से अधिक मामले पुलिस के खिलाफ आए हैं। इनमें से कम से कम 28 मामले चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ हैं। अधिकांश मामलों में एक से अधिक पुलिसकर्मी आरोपी के रूप में शामिल हैं। इनमें से 11 मामलों में आरोपी दोषी करार दिए जा चुके हैं जबकि बाकी मामलों में मुकदमा लंबित है। दोषियों में आईपीएस देशराज सिंह भी शामिल हैं। अदालत से किसी भी आरोपी पुलिसकर्मी को बरी नहीं किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में कुछ सह–आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत में सबसे नया मामला इंस्पेक्टर हरिंदर सेखों और उनकी पत्नी परमजीत कौर सेखों का है, जिन पर 16 फरवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।

2023 में दस दोषियों में चार पुलिसकर्मी शामिल

2023 में दस दोषियों में से चार दोषी पुलिसकर्मी थे। दोषी पुलिसकर्मियों में कांस्टेबल दिलबाज सिंह, एसआई सेवक सिंह, एसआई सुशील कुमार और हेड कांस्टेबल रितु बाला हैं। इसी साल पंजाब पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी राका गेरा को भी अदालत ने दोषी करार दिया था। राका गेरा का मामला सीबीआई अदालत में भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे पुराना मामला था। राका गेरा को सजा सुनाने के दौरान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जगजीत सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार समाज की जड़ों में इस कदर पैठ बना चुका है कि लोगों ने यह धारणा बनानी शुरू कर दी है कि किसी भी काम के लिए उन्हें किसी अधिकारी को रिश्वत देनी होगी। दोषी ऐसी सजा का हकदार है जो समाज में अन्य व्यक्तियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगी ताकि वे ऐसा अपराध करने से पहले दो बार सोचें।

42 लाख से अधिक पहुंची बीपीएल परिवारों की संख्या हरियाणा में

pMhx<A कांग्रेस विधायक आफताब अहमद की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सदन में बताया कि दिसंबर 2022 तक राज्य में 26 लाख 94 हजार 484 बीपीएल/एएवाई परिवार थे। आय सीमा में बढ़ोतरी के बाद इनकी संख्या दिसंबर 2023 तक बढ़कर 42 लाख 5 हजार 274 पहुंच गई है। यानि एक साल में 15 लाख से ज्यादा नये बीपीएल परिवार इस कैटेगरी में जुड़े हैं। सरकार ने बीपीएल परिवारों की आय सीमा एक लाख 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार कर दिया था। इससे बीपीएल लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई है। राज्य में लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत हरियाणा के लिए 66 हजार 250 मीट्रिक टन गेंहू आवंटित किया है।

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को बेस्ट निजी स्कूलों में पढने का मौका

pMhx<A पंजाब के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों के पास बेस्ट निजी स्कूलों में निशुल्क पढने का मौका है। केंद्र सरकार के सामा. जिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ के तहत ये सुविधा प्रदान की जाती है और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा श्रेष्ठ के जरिए बच्चों को चयन किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2024–25 सत्र के लिए परीक्षा अप्रैल माह में करवाने की तैयारी की जा रही है, इसलिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पंजाब (एससीईआरटी) की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि अनुसूचित जाति के अधिक संख्या के विद्यार्थियों के पास इस योजना का लाभ पहुंचे, इसलिए उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। कहा गया है कि आठवीं और दसवीं तक के विद्यार्थियों को जागरूक करने पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि वह योजना को अच्छी तरह समझकर परीक्षा उत्तीर्ण करके बेस्ट निजी स्कूलों में गुणवत्तापूवर्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा–निर्देश के संबंध में भी उन्हें जानकारी दी गई है।

योजना के तहत 9वीं व 11वीं तक के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में 12वीं तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन परामर्श व मेरिट के आधार पर ही स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ ही स्कूल प्रमुखों को भी इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

ये विद्यार्थी योजना का उठा सकेंगे लाभ

योजना के तहत अनुसूचित जाति के उन मेधावी गरीब विद्यार्थियों को 12वीं तक सीबीएसई से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश देना है, जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है। इसके अलावा इन विद्यार्थियों को केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना या मंत्रालय की उच्च श्रेणी शिक्षा योजना से भी जोड़ा जा सकता है।

इन मानकों के आधार पर स्कूलों किया गया चयन

इस योजना के तहत सीबीएसई से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी आवासीय स्कूलों का चयन एक समिति द्वारा तय मानकों के आधार पर ही किया जाता है।

समिति में शिक्षा मंत्रालय व सीबीएसई के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

उन स्कूलों को ही प्रवेश के लिए योजना में शामिल किया जाता है, जिनका पिछले 3 वर्षों से कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड का परिणाम 75 प्रतिशत अधिक हो। स्कूलों के पास 9वीं और 11वीं में एससी विद्यार्थियों के अतिरिक्ति प्रवेश के लिए पर्याप्त सुविधाएं हो।

आवासीय सुविधा (छात्रावास) वाले निजी स्कूलों में भोजन सहित स्कूल शुल्क व छात्रावास शुल्क का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाना है।

कांग्रेस व अकाली नेताओं ने साजिश के तहत तबाह किए सरकारी संस्थान : भगवंत मान

ekgkyhA पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज का लोकार्पण करने मोहाली पहुंचे सीएम भगवंत मान ने विरोधियों को जोरदार हमला बोला। राज्य की सरकारी संस्थाओं की बदहाली के लिए सीधे तौर पर अकाली और कांग्रेसी सरक. ारों को जिम्मेदार ठहराते हुए मान ने कहा कि उनकी सरकार अब सभी सरकारी संस्थाओं में अव्वल दर्जे की सहूलियत प्रदान कर रही है ताकि पंजाब का कोई भी व्यक्ति इन सहूलियतें का लाभ लेने से वंचित न रहे।

सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में नेता–मंत्री निजी संस्थानों के कारोबार में हिस्सेदार थे इसलिए इन संस्थानों को छूट दे रखी थी और इनसे कमीशन खाते थे। इससे सरकारी संस्थाओं की अनदेखी होती थी। अकाली व कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत पंजाब के स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचा खत्म कर दिया था। इन संस्थाओं के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो गए थे।

मजबूरन लोगों को निजी स्कूलों और अस्पतालों में जाना पड़ रहा था। निजी अस्पतालों में कैंसर का इलाज इतना महंगा था कि रोगी इलाज ही नहीं करवाते थे।

राज्य के लोग निराशा के आलम में चले गए थे। परिवारवाद के मोह में डूबे इन राजनीतिज्ञों को कभी पंजाब का दर्द नहीं समझा, इस कारण पंजाब के लोगों ने इनको घर बिठा दिया।

इन नेताओं को पंजाबी की परीक्षा पास करने की चुनौती दी

मुख्यमंत्री मान ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें पंजाबी तक नहीं आती थी, वे पंजाब के नंबरदार बन गए थे। अकाली नेता हरसिमरत बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नवजोत सिद्धू का नाम लेकर कहा कि वह शर्त लगाकर कहते हैं कि ये लोग पंजाबी का पेपर पास नहीं कर सकते।

मान ने कहा कि ये नेता कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े हैं, इन्हें पंजाबी भाषा की कोई जानकारी नहीं।

यदि वह इन नेताओं को सवालों के जवाब भी बता दें तो भी वह उत्तर सही नहीं लिख सकते। आगे कहा कि अकाली व कांग्रेसियों को लगता था राज्य में तीसरा पक्ष आ ही नहीं सकता।

अब पंजाबियों ने आप सरकार बनाकर इन्हें किनारे कर दिया है। सरकार लोगों की भलाई के लिए बड़े फैसले ले रही है तो बौखलाहट में आकर विरोधी नेता बिना वजह निंदा कर रहे हैं।

गैर भाजपा राज्य सरकारों से भेदभाव कर रही केंद्र

केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के फंड रोकने की सख्त आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गैर–भाजपा राज्य सरकारों के साथ नफरत और भेदभाव करती है जिस कारण पंजाब की तरह दिल्ली, केरल, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य अपने फंड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर हैं। मान ने कहा कि चुनाव में चंडीगढ़ के निगम चुनाव की तरह वोट न चुनी जाए। वहां बीजेपी के नुमाइंदे ने शहर के चुने हुए प्रति. निधियों के 36 वोटों का मजाक उड़ाया तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मान ने कहा कि पंजाब में 117 विधानसभा हलकों में से 92 विधायक आम आदमी पार्टी जीतकर आए हैं, जो साधारण घरों से संबंध रखते हैं। इन 92 विधायकों में से उनके सहित 82 विधायक पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में लोक सेवा के प्रति समर्पण भावना को योग्यता माना जाता है, जबकि विरोधी पार्टियों में परिवारवाद और निजता को प्राथमिकता दी जाती है।

दो साल में 40 हजार से अधिक सरक. ारी नौकरियां दीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने दो साल में 40 हजार से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दीं हैं, जो पंजाब के इतिहास में रिकॉर्ड है। कहा कि ये नौकरियां हासिल करने वालों में वह नौजवान भी शामिल हैं जो विदेश से लौटकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। नौजवानों के लिए रोजगार के बड़े मौके पैदा करने के लिए राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो साल में 70 हजार करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है, जिससे तीन लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं, जहां बच्चों को विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है।

तीन वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनेंगे

मान ने कहा कि होशियारपुर, कपूरथला और मोहाली एयरपोर्ट के पास मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास होंगे और नवीनतम तकनीकों से लैस होंगे। वहीं कहा कि मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, मगर वह वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम जैसी बात क्यों नहीं करते। मान ने कहा कि पंजाब में सरकार एक यूपीएससी सेंटर भी खोलने जा रही है।

ये एक बदलाव आहार में आपको हार्ट अटैक–डिमेंशिया जैसे गंभीर रोगों से दे सकती है सुरक्षा

तमाम अध्ययनों में आहार को स्वस्थ और पौष्टिक रखने पर जोर दिया जाता रहा है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि हम जिस तरह की चीजों का सेवन करते हैं उसका सेहत पर सीधा असर होता है। यही कारण है कि सभी लोगों को नियमित रूप से फलों–हरी सब्जियों के अधिक सेवन की सलाह दी जाती रही है।

हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, शरीर को रोगमुक्त रखने के लिए जरूरी है कि आप खाने के तेल में भी आवश्यक बदलाव करें।

तेल के सेहत पर होने वाले प्रभावों के बारे में जानने के लिए किए गए अध्ययन में शोधर्ताओं ने पाया कि अन्य खाद्य तेलों की जगह अगर ऑलिव ऑयल का सेवन किया जाए तो ये हमारे लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। इसके सेवन से न सिर्फ हृदय रोगों के खतरे को कम किया जा सकता है साथ ही ये डिमेंशिया जैसे गंभीर रोग से बचाने में भी मददगार साबित हो सकती है।

एक्स्ट्रा–वर्जिन ऑलिव ऑयल के फायदे

शोधकर्ताओं ने पाया कि एक्स्ट्रा–वर्जिन ऑलिव ऑयल किसी सुपरफूड से कम नहीं है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर मैरी लिन ने 20 से अधिक वर्षों तक ऑलिव ऑयल पर किए शोध में पाया कि वास्तव में ऐसा कोई अन्य भोजन नहीं है जो इस तरह के लाभ प्रदान करता हो।

वैज्ञानिकों ने माना कि अगर आहार में ये एक बदलाव कर लिया जाए तो कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने भी एक शोध में पाया कि जो लोग प्रतिदिन एक चम्मच भी ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं उनमें डिमेंशिया रोग से मरने का जोखिम उन लोगों की तुलना में 28 प्रतिशत कम होता है जिन्होंने कभी इसका सेवन नहीं किया।

क्या कहते हैं शोधकर्ता?

वैज्ञानिकों का कहना है, इस तेल में उच्च स्तर के लाभकारी यौगिक होते हैं, जिन्हें शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद माना गया है।

लाखों प्रतिभागियों पर किए अध्ययनों के विश्लेषण में पाया गया कि प्रतिदिन खाया जाने वाला प्रत्येक अतिरिक्त 5 ग्राम ऑलिव ऑयल (यानी एक चम्मच से थोड़ा अधिक) कई क्रोनिक बीमा. रियों से मरने के जोखिम को 4 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

एक्स्ट्रा–वर्जिन ऑलिव ऑयल पॉलीफेनोल्स से भरपूर होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में इंलामेशन को कम करने में काफी मददगार है।

क्लीवलैंड क्लिनिक में आहार और पोषण विशेषज्ञ क्रिस्टिन किर्कपैट्रिक कहते हैं, इंलामेशन कई गंभीर बीमा. रियों का आधार है।

अगर हम सूजन को आधार के रूप में देखते हैं, तो ऑलिव ऑयल हमें कई बीमारियों से बचा सकता है।

हार्ट के लिए फायदेमंद

सात देशों के अध्ययन में विशेष रूप से हृदय रोग पर ऑलिव ऑयल के प्रभावों पर ध्यान दिया गया। शोधकर्ताओं ने पाया इसमें हृदय–स्वस्थ को ठीक रखने वाले मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और पॉलीफेनोल्स की उच्च मात्रा होती है। ये दिल से संबंधित बीमारियों को कम करने और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थितियों से बचाने में भी मददगार हो सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, निश्चित मात्रा में पॉलीफेनोल वाले एक्स्ट्रा–वर्जिन ऑलिव ऑयल के विशेष लाभ हो सकते हैं।

डिमेंशिया रोग का कम होता है खतरा

इसी तरह हार्वर्ड वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में दावा किया है कि ऑलिव ऑयल से डिमेंशिया रोग का खतरा भी कम हो सकता है।

हार्वर्ड टी.एच. चौन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन की वार्षिक बैठक में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि आहार में इसे शामिल करने वाले लोगों में संज्ञानात्मक कार्य में वृद्धि देखी गई।

मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और डिमेंशिया के जोखिमों को कम करने में भी इससे मदद मिल सकती है।

हृदय रोगों का प्रमुख कारण धमनियों में प्लाक बनना रक्त वाहिकाओं को साफ रखने के लिए खाएं ये चीजें

स्वस्थ और पौष्टिक आहार सिर्फ शरीर को पोषण ही नहीं देते हैं, इससे शरीर निरोगी भी होता है। अध्ययनों में पाया गया है कि आहार में पर्याप्त पौष्टिकता का ध्यान रखकर कई प्रकार की बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ आहार में ही सुधार कर लें तो इससे करीब 40 फीसदी क्रोनिक बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। हृदय रोग–डायबिटीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में भी पौष्टिक आहार से लाभ मिल सकता है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि हृदय रोग के अधिकतर मामले धमनियों में प्लाक बनने से संबंधित होते हैं। प्लाक बनने से रक्त के सामान्य प्रवाह में बाधा आ जाती है, जिसके कारण हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है। इस तरह की समस्याओं से बचाव करने में भी आहार में सुधार करके विशेष लाभ पाया जा सकता है।

धमनियों में प्लाक से हृदय रोगों का खतरा

धमनियों में प्लाक बनने का मतलब धमनियों की भीतरी दीवारों पर वसायुक्त जमाव, कोलेस्ट्रॉल बढने से है। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है और यह विभिन्न हृदय रोगों का प्रमुख कारक मानी जाती है। आहार में गड़बड़ी के कारण वसा के जमाव का खतरा अधिक हो जाता है। गड़बड़ खानपान के कारण कम उम्र के लोगों में भी इस समस्या को तेजी से बढ़ते हुए देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ धमनियों में प्लाक को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सभी लोगों को आहार में इनकी मात्रा जरूर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

नट्स और स्वस्थ तेल

हृदय रोगों से बचाने और धमनियों को स्वस्थ रखने में नट्स के सेवन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बादाम और अखरोट जैसे मेवे स्वस्थ वसा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनसे बैड कोलेस्ट्रॉल और शरीर में सूजन की समस्या कम होती है। ज्यादातर नट्स में एल–आर्जिनिन नामक एमिनो एसिड होता है जो स्वस्थ रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में सहायक है।

नट्स की ही तरह खाने के लिए स्वस्थ तेल का चयन करना भी आवश्यक है। ऑलिव ऑयल में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट, शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मददगार हैं। ऑलिव ऑयल का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर और धमनियों में प्लाक बनने की समस्या कम हो सकती है।

हल्दी का करें सेवन

हल्दी को कई प्रकार से सेहत के लिए लाभकारी माना जाता रहा है। शोधकर्ता बताते हैं, हल्दी में करक्यूमिन नामक यौगिक होता है, जो एंटी–इंलामेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। यह धमनियों में सूजन को कम करने और प्लाक के निर्माण को रोकने में मददगार हो सकता है। करक्यूमिन को अध्ययनों में रक्त के थक्कों के जोखिम को कम करके, बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी फायदेमंद पाया गया है।

भोजन के अलावा रोजाना एक कप हल्दी वाले दूध के सेवन से शरीर को लाभ मिल सकता है।

लहसुन में होते हैं कारगर यौगिक

लहसुन हमारे किचन में मौजूद अति प्रभावी औषधि है जिसे एंटी–इंलामेटरी प्रभावों के लिए जाना जाता है। लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और धमनियों में प्लाक के निर्माण को रोकने में मदद करता है। रक्तचाप को कम करने, रक्त वाहिक. ाओं को स्वस्थ रखने और रक्त के थक्कों के जोखिम को कम करने में भी लहसुन के सेवन को लाभकारी पाया गया है। आहार में लहसुन को जरूर शामिल करें।

फ्रीजिंग वायरस से कोरोना के बाद अब नई महामारी को लेकर वैज्ञानिकों का अलर्ट, बन सकता है बड़ा खतरा

कोरोनावायरस पिछले चार साल से अधिक समय से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिमों का कारण बना हुआ है।

वैक्सीनेशन और हर्ड इम्युनिटी ने दुनियाभर में संक्रमण के कारण गंभीर रोगों के खतरे को तो कम कर दिया है, पर वायरस में म्यूटेशन और नए वैरिएंट्स के कारण संक्रमण की दर अब भी चिंता का कारण बनी हुई है। मसलन कोरा. ना महामारी को अब भी खत्म नहीं माना जा सकता है।

इस बीच वैज्ञानिकों ने दुनियाभर को एक नई संभावित महामारी को लेकर आगाह किया है।

वैज्ञानिकों ने अलर्ट किया है कि हमें एक नई और विचित्र महामारी के खतरे को लेकर अभी से सावधान रहना चाहिए।

इसके लिए जोंबी वायरस को संभावित कारण माना जा रहा है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि बर्फ के बड़े हिस्से के नीचे जोंबी वायरस मिलने की खबरें हैं, आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से ये वायरस निकल सकते हैं, जिससे एक बड़ी बीमारी का प्रकोप और नई वैश्विक चिकित्सा आपात की स्थिति पैदा होने का भी खतरा हो सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

जोंबी वायरस से संक्रमण का खतरा

ऐक्स–मार्सिले यूनिवर्सिटी में आनुवंशिकीविद् जीन–मिशेल क्लेवेरी कहते हैं, फिलहाल, महामारी के खतरों का विश्लेषण उन बीमारियों पर केंद्रित है जो दक्षिणी क्षेत्रों में उभर सकती हैं और फिर उत्तर में फैल सकती हैं।

ये वायरस मनुष्यों को संक्रमित करने और एक नई बीमारी का प्रकोप शुरू करने की क्षमता रखते हैं।

इरास्मस मेडिकल सेंटर के वायरोलॉजिस्ट मैरियन कूपमैन्स ने इससे सहमति जताई और कहा, हम नहीं जानते कि पर्माफ्रॉस्ट में कौन–कौन से वायरस पड़े हैं। हालांकि, मुझे लगता है कि यह बड़ा जोखिम है जो बीमारी फैलने में सक्षम हो सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण फैल सकता है वायरस

संक्रामक रोग विशेषज्ञ बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के साथ, कई ग्लेशियर और पर्माफ्रॉस्ट वर्षों से लगातार पिघल रहे हैं।

इस अपरिवर्तनीय पर्माफ्रॉस्ट पिघलन ने वर्षों से बर्फ में जमे कई बैक्टीरिया और वायरस को मुक्त कर दिया है। पिघली हुई बर्फ से पुनर्जीवित हुआ ऐसा ही एक वायरस है जॉम्बी वायरस।

इस प्रकार के वायरस बर्फ के अंदर फंसे रहने के कारण निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन ये फिर से सक्रिय होकर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।

हजारों साल पुराने वायरस हो सकते हैं फिर से सक्रिय

साल 2014 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने साइबेरिया में जीवित वायरस पर किए शोध में पाया कि वर्षों बाद भी ये वायरस एकल–को. शिका जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, भले ही वे हजारों वर्षों से पर्माफ्रॉस्ट में दबे हुए हों।

पिछले साल प्रकाशित शोध में बताया गया है कि साइबेरिया में सात अलग–अलग साइटों से कई वायरस के अस्तित्व का पता चला और जो मानवों में गंभीर रूप से संक्रमण का जोखिम बढ़ाने वाले हो सकते हैं।

एक वायरस का सैंपल 48,500 साल पुराना था, जो अब भी एक्टिव होकर गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकता है।

अलर्ट वैज्ञानिक पर

वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्माफ्रॉस्ट में ऐसे वायरस हो सकते हैं जो दस लाख साल तक पुराने हैं। प्रोफेसर क्लेवेरी कहते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कभी भी इन रोगाणुओं के संपर्क में नहीं रही होगी और यह एक और चिंता की बात है। एक अज्ञात वायरस के संपर्क में आने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर गंभीर असर हो सकता है, जैसा कि कोरोना की शुरुआत में देखा गया था।

फिर भी कोरोना के वैरिएंट्स दशक. ों पहले संक्रमण का कारण बन चुके थे। नए वायरस के कारण जोखिमों को कम करने, शुरुआती मामलों की पहचान और उन्हें स्थानीय स्तर पर ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम अभी से प्रयास कर रही है।

दुनिया का पहला ब्लड टेस्ट जिससे कैंसर का हो सकेगा शीघ्र निदान

कैंसर, वैश्विक स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, हर साल तमाम प्रकार के कैंसर के कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि दुनियाभर में पिछले एक दशक में ब्रेन कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि आई है। मस्तिष्क में कैंसरयुक्त असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि ट्यूमर का कारण बनती है जिससे ब्रेन कैंसर का खतरा हो सकता है। यह सबसे जानलेवा प्रकार के कैंसर में से एक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैंसर के कारण मृत्युदर अधिक होने का प्रमुख कारण समय पर इस रोग का निदान न हो पाना है। ज्यादातर लोगों में कैंसर का पता ही तब चल पाता है जब वह काफी बढ़ चुका होता है। दुनियाभर में बढ़ते कैंसर के जोखिमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।

ब्रेन कैंसर के शीघ्र निदान के उपायों की खोज कर रही वैज्ञानिकों की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सर्जनों और वैज्ञानिकों ने ब्रेन कैंसर के लिए दुनिया का पहला रक्त परीक्षण विक. सित किया है जिसकी मदद से समय रहते कैंसर का पता लगाया जा सकेगा।

समय रहते उपचार मिलने से रोगियों के जीवित रहने की दर को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

वर्षों से, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाना काफी कठिन प्रक्रिया रही है। हर साल दुनियाभर में हजारों लोगों को ये कैंसर प्रभावित करता है।

नोट- आप का सामना की हेल्थ,युवा सामना कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से पेशेवर पत्रकारों द्वारा बातचीत के आधार पर पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किये जाते है। आप का सामना लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है।

–डॉ० भीमराव अंबेडकर

संपादकीय

फिर नई उम्मीद असम में

विगत 29 दिसंबर को केंद्र, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा ने समझौते को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह राज्य में दशकों से चल रही हिंसा खत्म करेगा और विकास एवं समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी।

एक संप्रभु असम की मांग के साथ भारत राष्ट्र के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की घोषणा करते हुए 1979 में उल्फा का गठन किया गया था। तब से, इस सशस्त्र संघर्ष में दस हजार से अधिक लोगों की जान गई है, अनेक लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए और कई लोगों को अन्य प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। इसलिए असम की जनता लंबे समय से समस्या का राजनी. तिक समाधान चाहती रही है।

ऐसी ही एक पहल 2005 में हुई थी, जब उल्फा नेतृत्व द्वारा पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप (पीसीजी) नामक एक समूह का गठन किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉ. इंदिरा गोस्वामी के नेतृत्व में असमिया नागरिक समाज के सदस्य शामिल थे। समूह ने केंद्र सरकार के साथ कई दौर की चर्चा की। लेकिन 2009 में उल्फा प्रमुख अरि. बंद राजखोवा सहित संगठन के शीर्ष नेताओं को बांग्लादेश में गिरतार कर असम लाए जाने के बाद घटनाओं ने अलग मोड़ ले लिया। संगठन के कई महत्वपूर्ण नेता या तो सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरतार नेतृत्व ने 2011 में पीसीजी को मध्यस्थ न रखने और केंद्र सरकार के साथ सीधे वार्ता करने का फैसला किया। जबकि म्यांमार स्थित उल्फा के कमांडर इन चीफ और कट्टरवादी परेश बरुआ ने इसे असांविधानिक करार दिया।

हालांकि इस बीच उल्फा नेतृत्व ने, जिसे वार्ता समर्थक समूह कहा जाता है, असम के नागरिक समाज से कहा कि वे समस्या के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करें। उसके बाद मई, 2011 में प्रमुख बुद्धिजीवी हिरेन गोहेन के नेतृत्व में गुवाहाटी में नागरिक समाज ने सम्मेलन कर उल्फा नेतृत्व को केंद्र सरकार के समक्ष उठाई जाने वाली मांगों का एक चार्टर सौंपा। मांगों के चार्टर में राज्य में उत्पन्न राजस्व, प्राकृतिक संसाधनों, योजना प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए राज्य की शक्ति मजबूत करने और एक सुरक्षित जनसांख्यिकीय स्थिति के साथ–साथ त्वरित और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के माध्यम से असम (इसके लोगों) को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण देने के लिए सां. विधानिक संशोधन का प्रावधान शामिल था।

हालांकि, परेश बरुआ ने केंद्र सरकार के साथ चर्चा के महत्व को खारिज नहीं किया, लेकिन वह इस बात पर अड़े रहे कि चर्चा संगठन की मूल मांग–राजनी. तिक संप्रभुता और आर्थिक स्वायत्तता–पर होनी चाहिए। कई दौर की चर्चा के बाद हालिया संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेशक यह समझौता स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का वादा करता है, लेकिन यह कैसे किया जाएगा, यह बहुत स्पष्ट नहीं है।

लगता है कि बाकी के अधिकांश प्रावधान, जैसे–मतदाता सूची से अवैध विदे. शियों के नाम हटाने के लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की पुनरू जांच, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की पुनरू जांच (जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है), भूमि संबंधी आंकड़ों का डिजिटलीकरण, अवैध घुसपैठ को रो. कने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मजबूत निगरानी, भूमिहीन स्वदेशी लोगा. ं को जमीन देना आदि कोई नई बात नहीं है। इनमें से कुछ और राज्य में नई रेलवे लाइनों और राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना का जिक्र समझौते में किया गया है, जो सरकार के पहले से किए जा रहे कार्यों का ही विस्तार है। परेश बरुआ ने इस त्रिपक्षीय समझौते को शर्मनाकश और राज्य के लोगों के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि वह चर्चा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तब तक वार्ता की मेज पर नहीं बैठ सकते, जब तक असम की स्वायत्तता को मुद्दे पर चर्चा न हो। राज्य की जनता की प्रतिक्रिया भी बहुत ठंडी है। मीडिया और विपक्षी पार्टियां भी इसकी आलोचना कर रही है। उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के कुछ लोगों ने कहा कि वे समझौते की शर्तों से अनभिज्ञ थे और खुश नहीं हैं। वास्तव में समझौते की आलोचना इसलिए हो रही है, क्योंकि यह उल्फा के राजनीतिक मुद्दों को कमजोर करने वाले कुछ आर्थिक पैकेज तक ही सीमित है। वार्ता समर्थक गुट ने भी स्वीकार किया है कि वे अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद समझौते से अधिक कुछ हासिल नहीं कर सके। मौजूदा परिस्थितियों में वे अधिक सौदेबाजी करने की स्थिति में भी नहीं थे। इसलिए समझौते की सीमित सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके मौजूदा प्रावधानों को कैसे लागू किया जाता है।

सभी जानते हैं कि परेश बरुआ उल्फा की मुख्य ताकत बने हुए हैं। वह म्यांमार से ऑपरेशन चलाते हैं और हाल ही मीडिया में खबर आई कि असम के युवाओं में उनका साथ देने के लिए म्यांमार जाने का नया चलन शुरू हुआ है। वार्ता समर्थक गुट समेत सभी जानते हैं कि उल्फा समस्या का समाधान तभी होगा, जब परेश बरुआ चर्चा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा भी कई बार इसका संकेत दे चुके हैं। ताजा समझौते के पीछे मुख्यमंत्री की भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है। इस समझौते ने परेश बरुआ की प्रासंगिकता को खत्म करने का अवसर दिया था। ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए आलोचकों ने इस समझौते को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया समझौता बताया है। लेकिन जनता की प्रतिक्रिया देखते हुए लगता नहीं है कि इससे सत्तारूढ़ दल को कोई लाभ होगा।

समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ऊपरी असम में सुरक्षा बलों पर उल्फा के नए हमले हुए। कुछ उल्फा कैडर मारे गए और कुछ गिरतार हुए। यह नियंत्रण में रखने के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका का नतीजा है।

अंत नहीं विपक्ष की मुश्किलों का

स्वतंत्र भारत में यह पहली बार होगा, जब 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए ग्रांड ओल्ड कांग्रेस पार्टी 272 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में, अगर सैद्धांतिक तौर पर एकबारगी यह मान भी लिया जाए कि अप्रैल–मई, 2024 में कांग्रेस जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लडने की योजना बना रही है, उन सभी पर अगर उसे जीत हासिल हो, तब भी वह अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना सकती।

पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 499 में से 489 सीटों पर चुनाव लड़ा और 364 सीटें जीतीं। वर्ष 1957 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 494 सीटों पर चुनाव लड़ा और 371 सीटें जीतीं। इसी तरह, वर्ष 1962 में 494 में से 361 और 1967 में पहली बार अनुभवहीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी 523 लोकसभा सीटों में से 283 पर जीत हासिल कर सत्ता बरक. रार रखने में कामयाब रही। वर्ष 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदि. रा गांधी ने 518 सीटों में से 352 सीटें जीतकर जबर्दस्त वापसी की। वर्ष 1975 के आपातकाल के बाद मतदाताओं ने इंदिरा को सत्ता से बाहर का रास्ता जरूर दिखाया, पर कांग्रेस 154 सीटें जीतने में कामयाब रही।

वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने एक बार फिर विपक्ष को पटखनी देते हुए 353 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने दिसंबर, 1984 में 404 सीटें जीतकर कांग्रेस को बंपर जीत दिलाई। पंजाब में कांग्रेस की जीत से यह आंकड़ा 413 सीटों पर पहुंच गया, जहां चुनाव कुछ महीने बाद हुए थे। मगर 1989 में राजीव गांधी को शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन 197 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार के पतन के बाद कांग्रेस की फिर वापसी हुई। दरअसल, 1991 चुनाव के दौरान राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद कांग्रेस ने 244 सीटें जीतीं और छोटी पार्टियों के बाहरी समर्थन से पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनाई।

वर्ष 1996 में राव के नेतृत्व में कांग्रेस केवल 140 सीटें जीतकर सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस ने अल्पकालीन एचडी देवे गौड़ा और आईके गुजराल सरकारों को बाहर से समर्थन दिया। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने एनडीए की सरकार बनाई। तब भी कांग्रेस के पास 141 सीटें और भाजपा को 182 सीटें मिली थीं। वर्ष 1999 के मध्यावधि चुनावों में वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई, जबकि कांग्रेस 114 सीटों पर सिमट गई, जो ग्रांड ओल्ड पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। हालांकि 2004 में कांग्रेस ने अपनी स्थिति सुधारते हुए 145 सीटें जीतीं और एक ऐसा गठबंधन बनाया, जो न केवल 2004 में, बल्कि 2009 में भी सरकार बनाने में कामयाब रहा, जब कांग्रेस को 206 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में यह शायद आखिरी बार था, जब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के उदय ने कांग्रेस को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में दस फीसदी सीटें तक नहीं मिल सकीं। वर्ष 2014 में महज 44 सीटों पर सिमटना कांग्रेस के लिए शर्मनाक था। वहीं, 2019 में भी यह केवल 52 सीटें ही जीत पाई, जिसमें ज्यादातर सीटें केरल, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक से थीं।

मल्लिकार्जुन खरगे और तीनों गांधी (सोनिया, राहुल और प्रियंका) के संयुक्त नेतृत्व में, चुनावों में मिली लगातार हार और कमजोर आत्मविश्वास के चलते धूमिल संभावनाओं और अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट से जूझती कांग्रेस आप, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा (शरद पवार), द्रमुक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और 22 अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर भाजपा को हराने की जुगत कर रही है। पार्टी की पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम ने गठबंधन सहयोगियों से वार्ता के लिए पार्टी की रणनीति निर्धारित करने हेतु वासनिक के आवास पर बैठक की। पैनल के दो सदस्यों के अनुसार, उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वह गठबंधन के सहयोगियों से तीन सौ सीटें मांग सके। पैनल ने 292 लोकसभा सीटों को शॉर्टलिस्ट किया है, पर बारीकी से जांच करने पर ये 240 से भी कम निकली हैं। विभिन्न राज्यों की कई सीटें ऐसी हैं, जहां पार्टी के लिए गठबंधन सहयोगी के तौर पर चुनाव लडने का कोई आधार नहीं है।

यही नहीं, उनका विश्लेषण बताता है कि राहुल गांधी की आगामी भारत न्याय यात्रा में जिन राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों की 345 संसदीय सीटों में से केवल 15 सीटों पर ही कांग्रेसी सांसद हैं। व्यावहारिक तौर पर देखें, तो पता चलता है समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन करने पर भी कांग्रेस के लिए 50 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार करना कठिन होगा। कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं, जो राहुल की दूसरे चरण की यात्रा को निरर्थक, गलत और पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझती पार्टी के लिए नुकसानदायक मानते हैं। टीम खरगे समेत कोई भी इस स्थिति में नहीं है, जो राहुल को ईमानदार राय दे सके। हालांकि अपनी ओर से खरगे ने सीट बंटवारे की संभावनाओं पर चर्चा के लिए राज्यों के नेताओं को बुलाया है। इसमें संदेह नहीं कि जरूरत और मजबूरी का सिद्धांत कांग्रेस को सीट बंटवारे की ओर ले जा रहा है, क्योंकि वह अपने बल पर चुनाव लडने की स्थिति में नहीं है। हालांकि खरगे को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र में कम सीटों के कड़वे फॉर्मूले को स्वीकारने के लिए गांधी परिवार से काफी अनुनय और समर्थन की आवश्यकता होगी।

सहयोगी दल खुद को कमतर नहीं मानते और कोई रियायत देने को तैयार नहीं हैं। वास्तविकता से बेखबर कांग्रेसी नेताओं की समस्या यह है कि वे अतीत और पुरानी यादों में जीते हैं कि हमारे बाप–दादा ने घी खाया था, हमारी हथेली सूंघ लो। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को झटका लगना तय है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो नाजुक इंडिया गठबंधन का अराजक होना तय है।

ताकत अर्थव्यवस्था की

इन दिनों पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों से संबंधित दो खास बातें रेखांकित हो रही हैं। पहला, जहां प्रवासी भारतीय अर्थव्यवस्था को बल दे रहे हैं, वहीं भारत भी अपने प्रवासियों के हितों की रक्षा का प्रभावी हिमायती बना हुआ है। दूसरा, 28 दिसंबर को भारत ने कतर में जिन आठ नौसेना के पूर्व भारतीय अधिका. रियों की फांसी की सजा को घटवाने में कूटनीतिक भूमिका निभाई है, उनमें एक पूर्णेदु तिवारी भी हैं, जिन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन ऐंड डेवलपमेंट ब्रीफ्य रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, बीते वर्ष प्रवासी भारतीयों ने करीब 125 अरब डॉलर की धनराशि (रेमिटेंस) स्वदेश भेजी। रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत ने मेक्सिको, चीन और फिलिपींस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। शीर्ष पांच रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में भारत के अलावा मेक्सिको (67 अरब डॉलर) चीन (50 अरब डॉलर) फिलीपींस (40 अरब डॉलर) और मिस्र (24 अरब डॉलर) शामिल हैं। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि पहले जहां भारत से अकुशल श्रमिक कम आय वाले देशों में जाते थे, वहीं अब विदेश जाने वाले भारतीयों में उच्च कौशल वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उच्च आय वाले देशों में जा रहे हैं, जहां से वे अधिक धन भेज रहे हैं।

गौरतलब है कि जहां वर्ष 2022 में प्रवासी भारतीयों ने 100 अरब डॉलर की धनराशि स्वदेश भेजी, वहीं 2021 में 87 अरब डॉलर की राशि भेजी थी। जब वर्ष 2020 में कोविड–19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी की ऋणात्मक विकास दर की स्थिति में पहुंच गई थी, तब भी आर्थिक मुश्किलों के बीच भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई 83 अरब डॉलर की धनराशि से यहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला था। यह छोटी बात नहीं है कि प्रवासियों से धन प्राप्त करने वाले दुनिया के विभिन्न देशों की सूची में भारत वर्ष 2008 से अब तक पहले स्थान पर बना हुआ है। अतीत में जब भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट आई, प्रवासियों ने मुक्त हस्त से विद. ेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में सहयोग दिया है।

बीते वर्ष भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी–20 को अभूतपूर्व सफलता दिलाने में भी प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका रही है। विभिन्न देशों में संकटों के बीच फंसे भारतीय प्रवासियों को बचाने और भारत वापसी के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं। सरकार के मुता. बिक, विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सरकार की ओर से 2014 से दिसंबर, 2023 तक 626 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 3. 42 लाख भारतीयों की मदद की गई। वर्ष 2023 में इस्राइल और हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष में इस्राइल में फंसे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया है। जब वर्ष 2022 में रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में भारतीय समुदाय सीधे खतरे में आ गया था, तब ऑपरेशन गंगा के तहत बड़ी संख्या में भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया था।

अंबेडकर का बोर्ड लगाने पर रामपुर में बवाल फायरिंग में दलित छात्र की मौत

jkeij ;ihA रामपुर में मंगलवार देर शाम भीमराव अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हो गया। फायरिंग में 10वीं के छात्र की गोली लगने से मौत हो गई। छात्र के सिर में गोली लगी थी। जबकि 2 लोग घायल हैं। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी।

छात्र के परिजनों ने पुलिस और राजस्व कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शव को घटनास्थल पर रखकर विरोध प्रदर्शन करते रहे । परिजनों के विरोध पर पुलिस ने पिता की तहरीर पर 25 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा मध्य रात्रि 3 बजे दर्ज किया है। इसमें बड़ा गांव चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों और एसडीएम और तहसीलदार के हमराह पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने मृतक छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया है।

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नजरबंद

वहीं पीड़ितों से मिलने रामपुर आ रहे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने संभल में नजरबंद कर दिया गया है। इससे कार्यकर्ता और लोग गुस्से में हैं। उधर, मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम मिलक अमन देओल को निलंबित कर दिया गया है।

अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर दलित और गंगवार समाज के लोग आमने–सामने आ गए। इसके बाद पथराव शुरू हो गया।

अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर दलित और गंगवार समाज के लोग आमने–सामने आ गए। इसके बाद पथराव शुरू हो गया।

हंगामा की सूचना पर भारी संख्या में फोर्स के साथ अफसर मौके पर पहुंचे।

15 दिन पहले पुलिस ने हटवाया था कब्जा

घटना थाना मिलक क्षेत्र सिलईबड़ा गांव की है। यहां ग्राम समाज की जमीन है। इसे लेकर दलित और गंग. वार समाज के बीच विवाद चल रहा है। दरअसल, दलित समाज इस जमीन पर अंबडेकर की मूर्ति और बोर्ड लगाना चाहता है। मगर, गंगवार समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। 15 दिन पहले यह मामला पुलिस तक पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने इसे जमीन को खाली करवाया था।

सोमवार को कुछ लोगों ने जमीन पर अंबेडकर पार्क का बोर्ड लगाया दिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने–सामने आ गए। दोनों ओर से फायरिंग और पत्थरबाजी शुरू हो गई। विवाद बढने की सूचना पर मिलक थाने की फोर्स मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाने की हर कोशिश की। मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच फायरिंग में 17 साल के दलित छात्र सुमेश को गोली लग गई। उसकी मौके पर मौत हो गई। सुमेश सुबह ही 10 की परीक्षा देकर लौटा था। पथराव में अमित और रमन घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गांव वालों ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 10–10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है।

पुलिस वालों ने भागकर बचाई जान

इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलि. सवालों पर पथराव कर दिया। ष्ठस्क्क सहित अन्य पुलिस वालों ने भागकर जान बचाई। हालांकि, ग्रामीणों ने ष्ठस्क्क की गाड़ी और पुलिस कर्मियों की जीप को तोड़ दिया है। इससे के बाद दलित समाज के लोगों ने छात्र का शव रखकर सड़क जाम कर दिया। परिवार वालों ने राजस्वकर्मियों, पुलिस और गंगवार समाज पर हत्या का आरोप लगाया है।

मृतक छात्र के भाई ब्रज किशोर ने बताया कि मैं रिक्शा चलाकर आ रहा था। रास्ते में मैने खबर पढ़ी कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया। हमारी चौकी के दो पुलिस वाले जिसमें एक का नाम आदेश चौहान और एक का नाम ऋषिपाल है। यहां ऊपर चढ़े और यहां पर गंगवारों के कहने से उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर दी। दे दनादन उन्होंने फायरिंग की। जिसमें मेरे भैया सुमेश कुमार खत्म हो गए। मेरे पड़ोसी सहित तीन घायल हुए हैं।

मृतक के परिवार को एक करोड़ देने की मांग

मृतक के पिता गैंदनलाल की और से पुलिस को तहरीर दी गई है। तहरीर में पिता गैंदनलाल ने राजस्व कर्मियों और पुलिस सहित गंगवार समाज के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक सोमेश के परिवार को एक करोड़ रुपए और घायलों रमन बाबू और रहीस पाल को 10–10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना करने की मांग की है। हंगामे की सूचना मिलने पर मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय सिंह मौके पर पहुंचे। मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय सिंह ने कहा कि गोली लगने से एक युवक की मौत और दो लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया है कि घटना में जो भी दोषी होगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में स्थिति नियंत्रण में है। खाद के गड्ढे की जमीन पर पार्क बनाया जा रहा था। सारे बिंदुओं पर जांच की जाएगी। साथ ही पीएम रिपोर्ट आने पर स्थिति और साफ होगी। परिजनों की मांगों पर विचार किया जायेगा। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है।

पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने मृतक छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया है। परिजनों के विरोध पर पुलिस ने पिता की तहरीर पर 25 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा मध्य रात्रि दर्ज किया है। इसमें बड़ा गांव चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों और एसडीएम और तहसीलदार के हमराह पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कुर्मी गंगवार समाज के 19 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।

जाति और धर्म के आधार पर न सौंपे काम कैदियों को

ub fnYyhA गृह मंत्रालय के राज्यों और केंद्रशाति प्रदेशों से कहा कि जेल में बंद कैदियों को जाति और धर्म के आधार पर अलग न करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि भेदभावपूर्ण तरीके से जेल की रसोई के प्रबंधन जैसे काम सौंपना बंद करें। गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों के जेल मैनुअल में कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग करने का प्रावधान है और उन्हें उसके अनुसार जेलों में कार्य सौंपे जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है।

हर तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया– गृह मंत्रालय

जारी पत्र के मुताबिक, भारत का संविधान किसी भी भेदभाव पर रोक लगाता है। मॉडल जेल मैनुअल, 2016 गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रसारित किया गया है। मई 2016 में रसोई के प्रबंधन और भोजन पकाने में कैदियों के साथ जाति और धर्म आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

जेलों में जाति आधारित भेदभाव की अनुमति नहीं– गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कहा कि जेल मैनुअल में यह भी प्रावधान है कि सामा. जिक–आर्थिक स्थिति, जाति या वर्ग के आधार पर कैदियों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके जेल मैनुअल या जेल अधिनियम में ऐसे भेदभावपूर्ण प्रावधान नहीं होने चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रावधान मौजूद है, तो नियमावली या अधिनियम से भेदभावपूर्ण प्रावधान को संशोधित करने या हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

गृह मंत्रालय ने कहा कि वह समय–समय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह देता रहा है कि कैदियों की शारीरिक और मानसिक भलाई को महत्व दिया जाए। साथ ही कैदियों की चिकित्सा जांच की प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के लिए, मॉडल जेल मैनुअल 2016 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करता है।

पुतिन की पश्चिमी देशों को चेतावनी,परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए रूस पूरी तरह तैयार

e,LdkA रूस–यूक्रेन युद्ध के दो साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भड़ास निकाली है। पुतिन ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम वार्षिक संबा. धन में आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश परमाणु संघर्ष के हालात पैदा करना चाहते हैं, जो मानव सभ्यता को नष्ट कर देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश परमाणु युद्ध का श्वास्तविकश खतरा पैदा कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि रूस परमाणु हथियार उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार में हैं।

पुतिन ने आगाह किया है कि यूक्रेन युद्ध में दखलअंदाजी करने वालों के लिए परिणाम बहुत ही दुखद होंगे... उन्हें (पश्चिम) समझना चाहिए। मैंने उनसे कहा है कि हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो उनके क्षेत्रों पर लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस किसी को भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देगा।

पश्चिमी देशों को आड़े हाथ लेते हुए पुतिन ने कहा कि वे दावा कर रहे हैं कि रूस यूरोप पर हमले की योजना बना रहा है। मैं समझता हूं कि वे बकवास कर रहे हैं। वे खुद ही हमारे क्षेत्र पर हमले के लिए लक्ष्य की पहचान कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा, पश्चिमी देशों को यह समझना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो उनके क्षेत्र में लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। इन वजहों से वास्तव में परमाणु हथियारों के उपयोग के साथ संघर्ष और मानव सभ्यता के विनाश का खतरा है। क्या उन्हें (पश्चिम) यह समझ नहीं आता?

अमेरिका के साथ बातचीत के लिए रूस तैयार

पुतिन ने 15–17 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले देशवासियों को संबोधित किया। इस चुनाव में उनका अगले छह साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना जाना तय है। पुतिन ने रूस के विशाल अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रागार की सराहना की, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। रूसी समाच. ार एजेंसी तास के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस रणनीतिक स्थिरता पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से अलग अमे. रिका के साथ रणनीतिक स्थिरता वार्ताश की संभावना को खारिज कर दिया।

जातिगत जनगणना रिपोर्ट में कर्नाटक की क्या है, भाजपा के साथ कांग्रेस नेता क्यों कर रहे इसका विरोध?

ub fnYyhA बिहार के बाद कर्नाटक में जातिगत जनगणना रिपोर्ट पेश कर दी गई है। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को यह रिपोर्ट पेश की। भले ही रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। खुद सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के विधायकों ने इसका विरोध किया है। विपक्षी भाजपा ने भी जातिगत जनगणना रिपोर्ट पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।

इस बीच, राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वह भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। 2014 में सिद्धारमैया सरकार ने जातिगत सर्वे कराने का आदेश दिया था। आइये जानते हैं कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना रिपोर्ट को लेकर क्या हुआ है? रिपोर्ट में क्या–क्या शामिल है? इसको लेकर विवाद क्या है? भाजपा का क्या कहना है? इससे पहला किन राज्यों में इस तरह का सर्वे हुआ है?

कर्नाटक में जातिगत जनगणना रिपोर्ट को लेकर क्या हुआ है?

राज्य के ओबीसी आयोग ने 29 फरवरी को जातिगत जनगणना रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को सामाजिक आर्थिक सर्वे नाम दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने अपने कार्यालय के आखिरी दिन विधानसभा पहुंचे और सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की।

मीडिया से बात करते हुए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने कहा, हमने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने कहा कि वह इसे अगली कैबिनेट में पेश करेंगे और इसपर फैसला लेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

जातिगत जनगणना रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुसूचित जाति को सबसे अधिक आबादी वाला बताया गया है। दूसरे स्थान पर मुसलमानों को रखा गया है। इसके बाद क्रमश लिंगायत और वोक्कालिगा को रखा गया है।

जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है वो कई साल पुरानी है। दरअसल, 2014 में कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार एक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। यह सर्वे 127वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, ओबीसी के आनुपातिक आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए किया गया था।

दो वर्षों से जारी रूस–यूक्रेन युद्ध, हमने 31 हजार सैनिकों को खोया : जेलेंस्की

dhoA रूस–यूक्रेन युद्ध के दो साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को इन दो देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। दो साल की लड़ाई में दोनों देशों में बहुत कुछ बदल चुका है। इस युद्ध ने हजारों लोगों की जान ले ली, लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवारों और समुदायों को तोड़ दिया और अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। यह खूनी जंग रुकेगी, इसके भी कोई संकेत नहीं हैं। इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले के बाद से हमने अब तक अपने 31 हजार सैनिकों को खोया है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि वर्तमान में यूक्रेन के 18 फीसदी क्षेत्र पर रूस का कब्जा है।

p स्वामी,सम्पादक,प्रकाशक व मुद्रकः संतोष कुमार शुष्टा, आकाश व्यू, छकड़ायल रोड, कमला नगर, संजौली शिमला हि0 प्र0 – 171006 से प्रकाशित तथा सिग्मा प्रिंटर बलॉक न.6,शॉप न.170 एसडीए कॉम्पलेक्स कसुम्पटी शिमला से मुद्रित। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र शिमला ही मान्य होगा। मोबाईलः 09418453928,9805192400 e-mail: aapkasaamna@gmail.com